खबरों में रहे स्टॉक

ग्रैन्यूल्स इंडिया

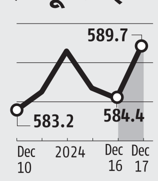

लिसडेक्सामफेटामाइन डाइमेसिलेट टैबलेट के लिए यूएसएफडीए मंजूरी

₹ 584.4 पिछला बंद भाव
₹ 589.7 आज का बंद भाव
0.9 % ▲

गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट्स इंडिया

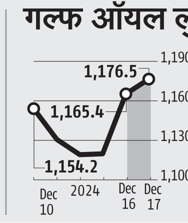

लुब्रिकेंट्स आपूर्ति के लिए पियाजियो समूह के साथ साझेदारी का नवीकरण

₹ 1,165.4 पिछला बंद भाव
₹ 1,176.5 आज का बंद भाव
0.9 % ▲

बेस्ट एग्रोलाइफ

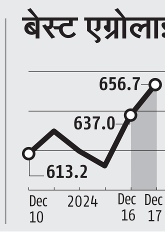

पेस्टिकल कंपोजिशन के लिए अफ्रीका के ओएपीआई से पेटेंट मिला

₹ 637.0 पिछला बंद भाव
₹ 656.7 आज का बंद भाव
3.1 % ▲

आरएमसी स्विचगियर्स

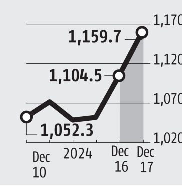

महाराष्ट्र में 5,000 सोलर पंपों के लिए 90 करोड़ रुपये का करार

₹ 1,104.5 पिछला बंद भाव
₹ 1,159.7 आज का बंद भाव
5.0 % ▲

जेनेसिस इंटरनैशनल कॉर्प

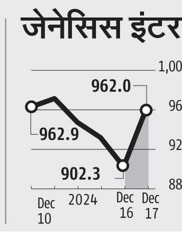

प. बंगाल में भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण की 56 करोड़ रुपये की परियोजना मिली

₹ 902.3 पिछला बंद भाव
₹ 962.0 आज का बंद भाव
6.6 % ▲

संक्षेप में

ओटीटी पर नशीले पदार्थों के प्रचार पर होगी कार्रवाई

सरकार ने ओटीटी मंचों को आगाह किया है कि यदि वे ऐसी सामग्री प्रसारित करते हुए पाए गए जो मुख्य पात्र और अन्य अभिनेताओं के माध्यम से नशीले पदार्थों के उपयोग को अनजाने में बढ़ावा देती है या उन्हें महिमामंडित करती है तो उनके खिलाफ नियामक संबंधी जांच की जाएगी। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने ओटीटी मंचों के लिए जारी किए गए परामर्श में कहा, 'इस तरह के चित्रण के, खासकर युवा और संवेदनशील दर्शकों पर संभावित प्रभाव के मद्देनजर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।' परामर्श में ओटीटी मंचों के लिए आचार संहिता का हवाला देते हुए उन्हें सामग्री की समीक्षा के दौरान उचित सावधानी बरतने और किसी भी कार्यक्रम में नशीले पदार्थों के उपयोग का चित्रण करते समय अस्वीकरण या उपयोगकर्ता चेतावनी जारी करने के लिए कहा गया है। *भाषा*

एंबेसी ऑफिस पार्क्स रीट ने 1,000 करोड़ रु जुटाए

एंबेसी ऑफिस पार्क्स रीट ने अपने बकाया ऋण के भुगतान के लिए गैर-परिवर्तनीय ऋणपत्र (एनसीडी) जारी कर 1,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। एंबेसी रीट ने शेयर बाजार को मंगलवार को दी सूचना में बताया, उसने 7.73 प्रतिशत की ब्याज दर पर पांच साल के ऋणपत्र के जरिये 1,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। इस राशि का इस्तेमाल कुछ मौजूदा ऋणों को चुकाने के लिए किया जाएगा। एंबेरी रीट के अंतरिम मुख्य कार्य अधिकारी ऋत्विक भट्टाचार्य ने कहा कि इस राशि को अत्यधिक प्रतिस्पर्धी दर पर जुटाया गया है। एंबेसी रीट भारत का पहला सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है। *भाषा*

गैर-सूचीबद्ध कंपनियां भी आगे

पिछले 5 वर्षों में गैर-सूचीबद्ध श्रेणी में 1 अरब डॉलर से ज्यादा राजस्व वाली कंपनियां बढ़ीं

समीर मुलगांवकर और सचिन मामपट्टा
मुंबई, 17 दिसंबर

वैश्विक महामारी के बाद सूचीबद्ध कंपनियों की आय में उछाल ने बाजारों को भले ही नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है, लेकिन भारत की गैर-सूचीबद्ध श्रेणी भी पीछे नहीं है।

कैपिटालाइन के आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि पिछले पांच वर्षों में गैर-सूचीबद्ध श्रेणी ने एक अरब डॉलर से अधिक राजस्व वाली कंपनियों की सूची में दर्जनों कंपनियों को जोड़ा है। वित्त वर्ष 20 में ऐसी 190 कंपनियां थीं। वित्त वर्ष 23 में इनकी संख्या बढ़कर 249 हो गई। वित्त वर्ष 24 के आंकड़े अभी जारी किए जा रहे हैं, लेकिन यह आंकड़ा पहले ही 153 तक पहुंच चुका है। मंगलवार की खबरों के मुताबिक ब्रोकरेज फर्म जीरोधा ने वित्त वर्ष 24 में एक अरब डॉलर का राजस्व पार कर लिया।

इस विश्लेषण में केवल उन कंपनियों पर विचार किया गया है, जिनका वर्ष मार्च में समाप्त होता है। कुछ कंपनियों का वर्ष दिसंबर में समाप्त होता है। उनका भी अरबों डॉलर का राजस्व है। इनमें महाराष्ट्र की हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज और नई दिल्ली की इंडिया यामाहा मोटर भी शामिल हैं।

ट्रेडिंग करने वाली कंपनियां अपनी

वित्त वर्ष 20 में एक अरब डॉलर से अधिक राजस्व वाली 190 कंपनियां थीं और वित्त वर्ष 23 में इनकी संख्या बढ़कर 249 हो गई

गतिविधियों की प्रकृति की वजह से बड़ा राजस्व दर्ज कर सकती हैं। इस विश्लेषण में एकरूपता के लिए दर्ज की गई शुद्ध बिक्री पर विचार किया गया, कारोबार की प्रकृति भले ही कुछ भी हो। इसमें इस अवधि के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपये मूल्य में बदलाव को भी ध्यान में रखा गया है।

प्रत्येक वर्ष की संख्या उन कंपनियों को दर्शाती है, जिनकी बिक्री उस समय प्रचलित विनिमय दर के अनुसार एक अरब डॉलर थी। भारत की मुद्रा पिछले कुछ वर्षों के दौरान कमजोर हुई है, जिसका मतलब है कि मुद्रा में नरमी की प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अरब डॉलर वाली कंपनियों में वृद्धि हुई है।

सूचना प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्र इस सूची में सबसे ऊपर है, जो कमजोर रुपये वाली स्थिति में तेजी से बढ़ सकते हैं। बीते वित्त वर्ष 2024 में उस श्रेणी में 16 कंपनियां थीं, जो इसका हिस्सा थीं। सूची में दूसरे स्थान पर ट्रेडिंग, उसके बाद वाहन, बीमा और विद्युत उत्पादन एवं वितरण कंपनियां शामिल थीं।

सूची में शामिल कुछ अन्य बड़ी कंपनियों में रिलायंस रिटेल और रिलायंस जियो जैसी गैर सूचीबद्ध कंपनियों की सहायक कंपनियां भी हैं, जिसकी सूचीबद्धता से पहले अटकलें लगाई जा रही थीं। अन्य प्रमुख कंपनियों में ई-कॉमर्स फर्म फ्लिपकार्ट (70,542 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री करने वाली कंपनी) और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऐपल इंडिया (66,728 करोड़ रुपये की शुद्ध बिक्री करने वाली कंपनी) का नाम शामिल है।

शीर्ष दस कंपनियों में से फ्लिपकार्ट इकलौती ऐसी कंपनी थी जिसने बीते वित्त वर्ष में घाटा दर्ज किया था। कंपनी का परिचालन घाटा 3,891 करोड़ रुपये और शुद्ध घाटा 4,248 करोड़ रुपये था।

भारत की सभी गैर सूचीबद्ध कंपनियों की जांच बढ़ रही है। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने भी निवेशकों को उन प्लेटफॉर्मों का उपयोग कर गैर सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर खरीदने और बेचने के प्रति चेताया है, जिन्होंने इस उद्देश्य के लिए लोकप्रियता हासिल की है।

9 दिसंबर को जारी बयान में कहा गया है, 'कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म अथवा वेबसाइटें सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की असूचीबद्ध प्रतिभूतियों में लेनदेन की सुविधा दे रही है। ऐसी गतिविधियां प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम 1956 और सेबी अधिनियम 1992 का उल्लंघन हैं।'

सांघी इंडस्ट्रीज और पेन्ना सीमेंट का अंबुजा सीमेंट्स में होगा विलय

अमृता पिल्लै
मुंबई, 17 दिसंबर

अदाणी समूह प्रवर्तित अंबुजा सीमेंट्स ने आज अपनी दो सहायक कंपनियों सांघी इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एसआईएल) और पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज लिमिटेड (पीसीआईएल) का अपने में विलय करने की घोषणा की है। कंपनी ने कहा कि दोनों सहायक कंपनियों के लिए अलग-अलग योजना बनाई गई है।

कंपनी ने कहा कि इस कवायद का उद्देश्य शेयरधारकों के लिए मूल्य बढ़ाना और संगठन की संरचना को व्यवस्थित करना एवं प्रभावी प्रशासन के लिए अनुपालन जरूरतों को आसान बनाना है। अंबुजा सीमेंट्स ने पिछले साल सांघी इंडस्ट्रीज और इस साल पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज के अधिग्रहण की घोषणा की थी। कंपनी ने अपने बयान में कहा है कि सूचीबद्ध इकाई सांघी इंडस्ट्रीज के लिए कंपनी के सभी पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक 100 शेयरों के लिए अंबुजा सीमेंट्स 2 रुपये अंकित मूल्य के साथ 12 शेयर जारी करेगी। इससे सांघी इंडस्ट्रीज के पात्र शेयरधारक अंबुजा सीमेंट्स के शेयरधारक बन जाएंगे। अंबुजा सीमेंट्स ने कहा कि अपेक्षित मंजूरी मिलने के बाद सांघी इंडस्ट्रीज का विलय 9 से 12 महीनों के भीतर पूरा हो जाएगा। अदाणी समूह के सीमेंट कारोबार के मुख्य कार्य अधिकारी अजय कपूर ने कहा कि इस विलय का उद्देश्य हमारी कंपनी को अधिक प्रतिस्पर्धी और कुशल बनाना है, जिससे शेयरधारकों का मूल्य बढ़े।

इसके अलावा अंबुजा सीमेंट्स ने कहा कि गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी पेन्ना सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए प्रस्तावित विलय के लिए वह अपने अलावा पेन्ना इंडस्ट्रीज के शेयरधारकों को पेन्ना इंडस्ट्रीज में प्रत्येक इक्विटी शेयर के लिए 321.50 रुपये का भुगतान करेगी। हालांकि, कंपनी ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये शेयरधारक कौन होंगे।

उल्लेखनीय है कि अंबुजा सीमेंट्स ने 2023 में 5,000 करोड़ रुपये के उद्यम मूल्य पर सांघी इंडस्ट्रीज में नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा की थी। फिलहाल, सांघी इंडस्ट्रीज की सालाना क्लिंकर क्षमता 66 लाख टन, सीमेंट क्षमता 61 लाख टन और चूना पत्थर का भंडार 1 अरब टन है।

डाइकिन इंडिया और रेची प्रिसिजन का संयुक्त उद्यम

शार्लीन डिसूज़ा
मुंबई, 17 दिसंबर

भारत में कंप्रेसर के विनिर्माण, डिजाइन और बिक्री पर नजर

डाइकिन इंडस्ट्रीज ने अपनी 100 प्रतिशत स्वामित्व वाली सहायक कंपनी डाइकिन एयरकंडीशनिंग (डाइकिन इंडिया) और ताइवान की कंप्रेसर कारोबार की दिग्गज कंपनी रेची प्रिसिजन कंपनी (रेची प्रिसिजन) के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने का ऐलान किया है। संयुक्त उद्यम के तहत भारत और कुछ विदेशी बाजार में रोटरी (इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर) कंप्रेसर का विनिर्माण, डिजाइन और बिक्री की जाएगी। दोनों कंपनियों ने संयुक्त विज्ञप्ति में यह जानकारी दी।

विज्ञप्ति में कहा गया, 'रेची प्रिसिजन की रोटरी कंप्रेसर की अभिनव तकनीक डाइकिन इंडिया के पोर्टफोलियो में सहायता करती है और बड़ा लाभ प्रदान करती है जिसमें देसी उत्पाद, सामर्थ्य क्षमता तथा व्यापक विश्वसनीयता शामिल है।' संयुक्त उद्यम के तहत डाइकिन इंडिया के पास बहुलांश हिस्सेदारी होगी। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस साझेदारी के शुरुआती चरण में भारत के एसी विनिर्माताओं को रेची ग्रुप के रोटरी कंप्रेसर (इन्वर्टर और नॉन-इन्वर्टर दोनों) के परीक्षण नमूने उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया जाएगा ताकि तेजी से इस्तेमाल और मूल्यांकन की सुविधा मिल सके। संयुक्त उद्यम वित्त वर्ष 25 की चौथी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है।

अकासा को एक और कारण बताओ नोटिस

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

संचालन मैनुअल को तय समयावधि में नहीं किया गया संशोधित

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को अकासा एयर को एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया। इसमें कहा गया है कि उसके उड़ान संचालन निदेशक ने छह महीने की अनिवार्य अवधि के भीतर संचालन मैनुअल को संशोधित नहीं किया। अधिकारियों ने आज यह जानकारी दी।

यह इस महीने अकासा एयर को डीजीसीए का दूसरा कारण बताओ नोटिस है। इस साल अगस्त में बेंगलूरु हवाई अड्डे पर जांच के दौरान 'खराब रखरखाव मानक' और 'खामियां' पाए जाने के बाद नियामक ने 9 दिसंबर को अकासा एयर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नियामक ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया है। 16 दिसंबर को नियामक ने इस विमानन कंपनी को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा कि संचालन मैनुअल का संशोधन चक्र छह महीने से ज्यादा हो गया है, नहीं हुआ है जो डीजीसीए नियमों का उल्लंघन है। अधिकारियों ने कहा कि यह सुनिश्चित करना उड़ान संचालन निदेशक की जिम्मेदारी थी कि इन नियमों का पालन किया जाए। डीजीसीए ने इस नोटिस का जवाब देने के लिए कंपनी को 14 दिन का समय दिया है।

किसी भी विमानन कंपनी के परिचालन में सुरक्षा, नियामकीय अनुपालन और मानकीकृत प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के लिए संचालन मैनुअल महत्वपूर्ण होती है। नियामकीय अपडेट को शामिल करने, परिचालन संबंधी बदलावों को पूरा करने और जांच या घटनाओं से सीखे गए सबक को शामिल करने के लिए अर्ध-वार्षिक संशोधन अनिवार्य होता है। इसे अपडेट करने में विफल रहने से सुरक्षा और अनुपालन का जोखिम होता है, जिससे डीजीसीए के दंड की आशंका रहती है। अगस्त 2022 में वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन करने वाली अकासा एयर के पास 26 विमानों का बेड़ा है।

वैकल्पिक परिसंपत्तियों में होगा 5 गुना इजाफा

पीरजादा अबरार
बेंगलूरु, 17 दिसंबर

देश में वैकल्पिक परिसंपत्ति बाजार इस समय करीब 400 अरब डॉलर एयूएम (प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां) का है। इसके साल 2034 तक पांच गुना बढ़कर दो लाख करोड़ डॉलर हो जाने का अनुमान है। यह उछाल निवेशकों के बढ़ते अनुभव, पोर्टफोलियो में विविधता की जरूरत और मददगार नियामकीय विकासों के बल पर होगी। एवेंडस कैपिटल के अध्ययन इंडिया गोज अल्टरनेटिव्स में यह जानकारी दी गई है।

अध्ययन में भारत में वैकल्पिक परिसंपत्तियों की वृद्धि की महत्वपूर्ण क्षमता को बताया गया है। देश में तेजी से बढ़ रहे धनाढ्य लोग (एचएनआई) लगातार वैकल्पिक परिसंपत्तियों का रुख कर रहे हैं।

अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में वैकल्पिक निवेश पारंपरिक निवेश के विकल्पों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे देश के धनाढ्य और अति धनाढ्य लोगों वाली श्रेणियों की रुचि ज्यादा बढ़ रही है। यह रुझान वैश्विक

एवेंडस कैपिटल के अध्ययन से पता चला है कि धनाढ्य लोगों की बढ़ती संख्या से वैश्विक वित्तीय संपत्ति की वृद्धि को मिल रही रफ्तार

रुख के अनुरूप है, जहां साल 2005 से 2020 के बीच कुल वैश्विक एयूएम में विकल्पों की हिस्सेदारी 10 प्रतिशत से दोगुनी होकर 20 प्रतिशत हो गई है।

एवेंडस कैपिटल के प्रबंध निदेशक और सह-प्रमुख (उपभोक्ता, एफआईजी और कारोबारी सेवा निवेश बैंकिंग) अंशुल अग्रवाल ने कहा, 'भारत में वैकल्पिक निवेश का उभार हमारे निवेश परिदृश्य में मौलिक बदलाव को बताता है। हम पूंजी लगाने के तरीके में बुनियादी बदलाव देख रहे हैं। यह बदलाव नियामकीय संवर्द्धन, तकनीकी प्रगति और अनुभवी निवेशकों के बढ़ते आधार के बीच तालमेल से संचालित हो रहा है।'

एवेंडस कैपिटल की निदेशक (उपभोक्ता, एफआईजी और कारोबारी सेवा निवेश बैंकिंग) स्निग्धा खेमका ने कहा, 'वैकल्पिक निवेश भारतीय निवेश यात्रा में अगले चरण का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे भारत के 10 लाख करोड़ डॉलर के जीडीपी की राह में प्रमुख उत्प्रेरक का काम करने वाले हैं। हम कई वैकल्पिक निवेश फर्मों को भारत को लेकर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए देख रहे हैं, जो विकास के अगले दौर के लिए तैयार है जिसमें विविधीकरण महत्वपूर्ण होगा।'

मारुति ने 1 साल में बनाईं 20 लाख कारें

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 17 दिसंबर

मारुति सुजूकी इंडिया (एमएसआईएल) ने आज ऐलान किया उसने इस साल पहली बार 20 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया है। पिछले साल देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता ने 19.34 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया था। कंपनी ने कहा, '20 लाख गाड़ियों में से करीब 60 फीसदी गाड़ियों का विनिर्माण हरियाणा और 40 फीसदी गाड़ियां गुजरात में बनाई गई हैं। इस साल बलेनो, फ्रॉन्क्स, अर्टिगा, वैगन आर और ब्रेजा शीर्ष पांच विनिर्मित गाड़ियां थीं।' इसमें कहा गया है कि हरियाणा के मानेसर संयंत्र से विनिर्मित अर्टिगा 20 लाखवीं गाड़ी थी।

मारुति सुजूकी के पास फिलहाल तीन संयंत्र हैं। इनमें से दो हरियाणा (गुड़गांव और मानेसर) और एक गुजरात के हंसलपुर में है। इन सभी संयंत्रों से कुल मिलाकर सालाना 23.5 लाख गाड़ियों के विनिर्माण की क्षमता है।

2025 में ईवी से धमाल मचाएंगी वाहन कंपनियां

पृष्ठ 1 का शेष

भारतीय वाहन बाजार में ईवी एक तरह से अभी तक घुटने ही चल रहे हैं। इक्रा लिमिटेड में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीकुमार कृष्णमूर्ति ने माना कि यात्री वाहन श्रेणी में ईवी की पैठ बहुत कम है। उन्होंने कहा, 'वित्त वर्ष 2024 में यात्री वाहन बाजार में ईवी की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी थी, जो इस वित्त वर्ष में बढ़कर 3 फीसदी हो सकती है। अभी तो मामला बहुत धीमे बढ़ रहा है मगर दूर तक नजर डालें तो तस्वीर काफी उजली नजर आती है।'

विशेषज्ञों को लगता है कि भारत में यात्री वाहनों के इलेक्ट्रिक बनने का सफर अभी शुरुआती चरण में ही है। दोपहिया में तो इलेक्ट्रिक स्कूटर रफ्तार पकड़ चुके हैं मगर यात्री कारों में ईवी की रफ्तार बहुत धीमी है। हां, यह धीरे-धीरे बढ़कर 2030 तक 15 फीसदी हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं बशर्ते अच्छे उत्पाद आएं और उपभोक्ताओं की दिलचस्पी वैकल्पिक तकनीकों में बढ़ती जाए। कृष्णमूर्ति ने कहा कि इसका फायदा शुरुआत में हाइब्रिड वाहनों को मिल सकता है मगर तकनीक बेहतर होने पर ग्राहक ईवी को पूरी तरह अपनाने लगेंगे।

इसमें खर्च करने लायक आय बढ़ने, ग्राहकों की पसंद बदलने और चार्जिंग ढांचे में निवेश बढ़ने का भी हाथ रहेगा। सरकारी नीतियां भी इसे रफ्तार देंगी। मगर फिलहाल को ईवी उद्योग गाड़ियों की ऊंची कीमत, डीलरों के पास लंबे अरसे तक गाड़ियां अटके रहने और खरीदार के लिए गाड़ी रखने का खर्च ज्यादा होने जैसी चुनौतियों से जूझ रहा है। विश्लेषक बताते हैं कि ईवी बाजार बढ़ाना है तो मजबूत उत्पाद लाने होंगे और चार्जिंग तथा सर्विसिंग का नेटवर्क बेहतर करना होगा।

2024 में कई बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार आई थीं, जिनमें टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी का इलेक्ट्रिक मॉडल पंच ईवी भी शामिल था। इसमें बैटरी के दो तरह के विकल्प थे, जो एक बार में चार्ज होने पर 421 किलोमीटर तक दौड़ सकते थे।

लक्जरी गाड़ियों में बीएमडब्ल्यू ने आई5 इलेक्ट्रिक सिडैन उतारी। कंपनी का दावा है कि यह एक चार्ज में 516 किमी चल जाती है। किया भी अपनी मशहूर ईवी9 भारत ले आई और एमजी मोटर ने बैटरी का सबस्क्रिप्शन अलग से देने वाली विंडसर ईवी उतारी।

Piramal Capital & Housing Finance

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड
(CIN: U65910MH1984PLC032639)
(पूर्व में दीवान हाउसिंग फाइनैंस कॉरपोरेशन लि. के नाम से ज्ञात)
पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 601, छठवीं मंजिल, अमिटी बिल्डिंग, पीरामल अगस्ता कॉरपोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के विपरीत, एलबीएस मार्ग, कुर्ला (वेस्ट), मुम्बई-400 070
सम्पर्क व्यक्तिः बीनू कोरेमबेथ/गुरविंदर गुजराल
वेबसाइटः www.piramalfinance.com

पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड की अशोध्य ऋण/अनर्जक सम्पत्ति युक्त प्रत्याभूत एवं गैर-प्रत्याभूत निवेश सूची की सुपुर्दगी के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (स्वीस चैलेंज) हेतु आमंत्रण

1. पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड (पीसीएचएफएल) "स्वीस चैलेंज पद्धति" के अंतर्गत **"अनर्जक सम्पत्तियों"** के रूप में सार्वजनिक सूचना दस्तावेज में तथा यहां उल्लेखित अपनी वित्तीय सम्पत्तियों (अनर्जक अथवा अशोध्य ऋण) की बिक्री के लिए पात्र एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनियों ("एआरसी")/बैंकों/वित्तीय संस्थानों/एनबीएफसी से इच्छा की अभिव्यक्ति ("ईओआई") आमंत्रित करती है, जो नीचे उल्लेखित सम्पूर्ण क्रय मूल्य पर अधिग्रहण के लिए बोलीदाता से हाथों में उपलब्ध एक वर्तमान प्रस्ताव पर आधारित हैः

निवेश सूची	मूल बकाया (रु. करोड़ में)	एंकर बोली (रु. करोड़ में)
प्रत्याभूत	236	98
गैर-प्रत्याभूत	314	23
कुल	550	118

2. क्रय मूल्य का नकदी यानी 100 प्रतिशत नकदी आधार पर अग्रिम भुगतान करना होगा।
3. बिक्री के लिए अनर्जक सम्पत्तियों का कुल मूल बकाया 30 नवम्बर 2024 को लगभग रु. 5,500,000.00 (भारतीय रुपये में पांच सौ पचास करोड़ मात्र) है।
4. कृपया ध्यान दें कि पूलों के लिए मूल्य प्रत्याभूत तथा गैर-प्रत्याभूत अनर्जक सम्पत्तियों के लिए अलग-अलग प्रदत्त किया गया है, परंतु सम्पत्तियों के दोनों पूलों (जैसा कि पीसीएचएफएल द्वारा चिन्हित किया गया है) के लिए मूल्य वर्द्धित बोली प्रस्ताव प्रदत्त करने वाले पात्र क्रेता को प्राथमिकता दी जाएगी। बिक्री सार्वजनिक सूचना दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार तथा उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संचालित की जाएगी। पात्र इच्छुक आवेदकगण पीसीएचएफएल की वेबसाइट (www.piramalfinance.com) पर सार्वजनिक सूचना दस्तावेज देख सकते हैं।
पात्र इच्छुक आवेदक को सार्वजनिक सूचना दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के जरिए रु. 1,00,00,000/- (भारतीय रुपये में एक करोड़ मात्र) की रकम का बयाना राशि जमा ("ईएमडी") जमा करना होगा।
5. अनर्जक सम्पत्तियों की "जैसे है जहां है", "जैसे है जो है", "वहां जो कुछ है" तथा "बिना किसी दायित्व" के आधार पर सिर्फ "100 प्रतिशत नकदी आधार" पर बिक्री की जाएगी।
6. सार्वजनिक सूचना दस्तावेज में निर्धारित नियम एवं शर्तों के अनुसार बिक्री की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए तथा अनर्जक सम्पत्तियों के विवरण की जानकारी हासिल करने के लिए इच्छुक कोई भी पार्टी 27 दिसम्बर, 2024 को अथवा उससे पहले ईएमडी जमा कर, आशय पत्र, गैर-प्रकटन अनुबंध, प्रपत्र 29(ए) आईबीसी का निष्पादन कर एवं प्रस्तुत कर अपनी इच्छा अभिव्यक्त कर सकते हैं।
7. पीसीएचएफएल के पास बिना कोई कारण बताए कथित बिक्री के नियम एवं शर्तों में बदलाव, संशोधन अथवा पूल के आकार एवं गठन में परिवर्तन, तथा/अथवा लेनदेन के किसी भी चरण प्रस्तावित बिक्री रद्द करने का अधिकार सुरक्षित है। 27 दिसम्बर, 2024 को अथवा उससे पहले कोई भी मूल्य वृद्धि बोली/प्रस्ताव के प्राप्त नहीं होने पर पीसीएचएफएल के पास चिन्हित मूल कीमत प्रस्तावित करने वाले बोलीदाता के साथ अनर्जक सम्पत्तियों की बिक्री सम्पन्न करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में पीसीएचएफएल का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी एवं निर्णयात्मक होगा। कृपया ध्यान दें कि बिक्री पीसीएचएफएल द्वारा अंतिम अनुमोदन का विषय वस्तु होगा।
आगे के विवरण के लिए ऊपर उल्लेखित कार्यालय के विवरण में उल्लेखित अधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें।

दिनांक : 18.12.2024 हस्ता/-, अधिकृत अधिकारी,
स्थान : मुंबई पीरामल कैपिटल एण्ड हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड

निफ्टी 100 कंपनियों का बढ़ रहा बोर्ड

कृष्ण कांत
मुंबई, 17 दिसंबर

कॉरपोरेट गवर्नेंस मानकों के सख्त होने और नियामकीय अनुपालन बढ़ने से देश की बड़ी सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल (बोर्ड) में लगातार विस्तार हो रहा है। कॉरपोरेट गवर्नेंस पर एक्सीलेंस एनेबलर्स सर्वे के पांचवें संस्करण के मुताबिक निफ्टी 100 कंपनियों के निदेशक मंडल में वित्त वर्ष 24 तक औसतन 10.52 सदस्य थे जबकि वित्त वर्ष 21 में यह संख्या 9.86 और वित्त वर्ष 23 में 10.48 थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के पूर्व चेयरमैन एम दामोदरन की अगुआई में यह पहल की गई थी।

सर्वेक्षण के 2024 संस्करण से पता चलता है कि वित्त वर्ष 24 में निफ्टी 100 कंपनियों में से 14 प्रतिशत में 14 या उससे अधिक निदेशक थे। वित्त वर्ष 21 में ऐसी 8 और वित्त वर्ष 23 में 11 कंपनियां थीं। इस बीच 61 कंपनियों ने वित्त वर्ष 24 में नौ से 13 निदेशक होने की सूचना दी जबकि वित्त वर्ष 23 में कंपनियों की संख्या 65 थी। इस तरह ऐसी कंपनियों के मामले में कुछ गिरावट आई। लेकिन वित्त वर्ष 21 की 57 कंपनियों के मुकाबले में इसमें इजाफा हुआ। परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 24 में निफ्टी 100 कंपनियों में से 75 प्रतिशत कंपनियों में 9 या उससे ज्यादा निदेशक थे जबकि वित्त वर्ष 21 में यह संख्या 65 प्रतिशत थी।

सर्वेक्षण में बड़े निदेशक मंडल के फायदों पर प्रकाश डाला गया है और इस बात पर जोर दिया गया कि आकार का निदेशक मंडल के प्रदर्शन और प्रभावशीलता पर महत्त्वपूर्ण रूप से असर पड़ता है। सर्वेक्षण में कहा गया है, 'निदेशक मंडल की पांच अनिवार्य समितियां होने से निदेशक मंडल के पर्याप्त सदस्य होना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि समितियों का ठीक से गठन हुआ है और लगभग सभी समितियों में एक जैसे सदस्य नहीं हैं। साथ ही सूचनाओं में तालमेल भी रहेगा वरना समितियों में नहीं होने वालों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।'

सेबी के नियमों में यह प्रावधान है कि

इन कंपनियों के निदेशक मंडल में महिलाओं और स्वतंत्र निदेशकों की संख्या में इजाफा हुआ है

शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों (1 अप्रैल, 2019 से लागू) और शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध कंपनियों (1 अप्रैल, 2020 से प्रभावी) के निदेशक मंडल में कम से कम छह निदेशक जरूर होने चाहिए। एक को छोड़कर सभी निफ्टी 100 कंपनियां इस अनिवार्यता का अनुपालन करती हैं।

नियामकीय आवश्यकताओं और बाहरी दृष्टिकोणों की बढ़ती मांग के अनुरूप कंपनियां अधिक संख्या में गैर-कार्यकारी निदेशकों (एनईडी) की नियुक्ति कर रही हैं। सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में निफ्टी 100 कंपनियों में से 99 प्रतिशत में गैर-कार्यकारी निदेशकों की हिस्सेदारी आधी से अधिक थी। वित्त वर्ष 21 में 84 प्रतिशत कंपनियों में यह स्थिति थी।

इसी तरह निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों (आईडी) की संख्या में वृद्धि हुई है क्योंकि अधिकांश कंपनियां स्वतंत्र निदेशकों के प्रतिनिधित्व के संबंध में सेबी के मानदंडों का पालन कर रही हैं। वित्त वर्ष 24 में निफ्टी 100 की 81 कंपनियों में स्वतंत्र निदेशकों की हिस्सेदारी 50 प्रतिशत या उससे अधिक थी जबकि वित्त वर्ष 21 में 63 और वित्त वर्ष 23 में 77 कंपनियां ऐसी थीं। महिला-पुरुष विविधता के संबंध में भी प्रगति हुई है। निफ्टी 100 कंपनियों ने वित्त वर्ष 24 में 200 महिला निदेशकों की सूचना दी जबकि वित्त वर्ष 21 में यह संख्या 158 और वित्त वर्ष 23 में 193 थी। इनमें से 73.5 प्रतिशत स्वतंत्र निदेशक थीं।

मुंबई संस्करण: बिज़नेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता खेओरा द्वारा मै. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीघा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल\ आरएनआई नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 033-22101314/1022/1600 फैक्स - 033-22101599
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं